

# Daily Current Affairs

Date : 30 April, 2026

UTKARSH  
CLASSES

CIVIL  
SERVICES

## अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल-टाइम सिस्टम (SMART)
2.	राजस्थान में दुग्ध उत्पादन का कृषि क्षेत्र में योगदान
3.	अंतरराष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव - 2026
4.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. जवाई लेपर्ड रिजर्व क्षेत्र में नए निर्माण पर रोक 2. राजस्थान पुलिस का विशेष अभियान 'मिशन जागृति' 3. 16-कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परीक्षण 4. यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम 5. 'मन की बात' के 133वें संस्करण में 'गोडावण' का विशेष उल्लेख 6. ऑपरेशन प्रवर्तन 7. रीको द्वारा 12 नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना 8. डॉ. लोकेश सैनी : ए.बी. बेकर टीचर रिकग्निशन अवॉर्ड 9. अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय हैंडबॉल (पुरुष) चैंपियनशिप 2025-26
5.	शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम
6.	INS कल्पेनी
7.	जैविक खेती
8.	भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG)
9.	एशिया-प्रशांत फोरम
10.	चांगी नौसैनिक अड्डा
11.	सिंधु जल संधि
12.	OPEC एवं OPEC+
13.	2026 शंघाई सहयोग संगठन (SCO) रक्षा मंत्रियों की बैठक
14.	झील: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट

--:1:--



## राजस्थान परिदृश्य



### सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल-टाइम सिस्टम (SMART)



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने DOIT&C द्वारा राज्य में कार्यान्वित 'सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल-टाइम सिस्टम (SMART)' की व्यापक समीक्षा की।

DOIT.C Department of Information Technology & Communications, Rajasthan

राज काज

SMART GOVERNANCE EASY EXECUTION

ANYTIME AND ANYWHERE ACCESS  
With the Rajkaj Mobile App

INSTANT NOTIFICATION FOR EVERY new e-File In your Inbox

GET SMS REMINDERS twice daily for pending actions 9:30 AM & 6:30 PM

TRACK YOUR E-FILE AND E-DAK pendency with ease

READ, APPROVE AND SIGN Drafts added In e-File

WORKS MADE Easier...



मुख्य बिन्दु:

- कार्यान्वयन : राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (DOIT&C) के अंतर्गत राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (RISL) द्वारा।
- मुख्य उद्देश्य : सरकारी सेवाओं और लाभों के वितरण को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) के माध्यम से स्वचालित और बेहतर बनाना।

--2--

# Daily Current Affairs

Date : 30 April, 2026



- यह प्रोजेक्ट विशेष रूप से 'राजस्थान अनुग्रह सेवा प्रदायगी अधिनियम' के विजन को धरातल पर उतारने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

## प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- **स्वचालित पहचान** : यह सिस्टम डेटा एनालिटिक्स और AI का उपयोग करके उन नागरिकों की पहचान करता है, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए पात्र हैं, ताकि उन्हें मैनुअल आवेदन के बिना लाभ मिल सके।
- **रियल-टाइम सेवा वितरण** : पात्र लाभार्थियों को वास्तविक समय में लाभ पहुँचाने के लिए सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है, जिससे देरी कम होती है और पारदर्शिता बढ़ती है।
- **सेंट्रल डेटा रिपॉजिटरी** : यह सिस्टम राजस्थान के निवासियों के डेटा लेक पर आधारित है, जहाँ AI/ML तकनीकों का उपयोग करके गलत लाभार्थियों की पहचान की जाती है और छूटे हुए वास्तविक लाभार्थियों को जोड़ा जाता है।

--3--

## राजस्थान में दुग्ध उत्पादन का कृषि क्षेत्र में योगदान

### चर्चा में क्यों?

- राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, पशुधन क्षेत्र का वर्ष 2025-26 में प्रचलित कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन (GVA) ₹2.17 लाख करोड़ (लगभग) है।

**राजस्थान**

**राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार:**

- राज्य में दुग्ध संकलन वर्ष 2025-26 में बढ़कर लगभग **45 लाख लीटर प्रतिदिन**।
- दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता दो वर्षों में 51 लाख लीटर से बढ़कर **54 लाख लीटर प्रतिदिन**।
- 'बेसिक एनीमल हस्बैंडरी स्टैटिस्टिक्स (BAHS) 2025' रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सम्पूर्ण देश में दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर।

### मुख्य बिन्दु:

- यह कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कुल योगदान का लगभग 49.35 प्रतिशत है, जो फसलों के हिस्से (42.61 प्रतिशत) से अधिक है और राज्य में ग्रामीण आजीविका के लिए एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है।
- राजस्थान में पशुपालन को सामान्यतया 'किसान का ATM' की संज्ञा दी जाती है।

---4---

## राज्य में दुग्ध उत्पादन :

- राज्य में दुग्ध संकलन (वर्ष 2025-26 में) : लगभग 45 लाख लीटर प्रतिदिन।
- दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता : विगत 2 वर्ष में 51 लाख लीटर से बढ़कर 54 लाख लीटर प्रतिदिन।
- डेयरी के मार्केटिंग नेटवर्क में व्यापक विस्तार से दुग्ध उत्पादों के विपणन में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में नए 'सरस' बूथ स्थापित किए जाने के साथ ही अन्य राज्यों में प्रतिदिन 1 लाख लीटर से अधिक दूध की आपूर्ति की जा रही है।
- सरस द्वारा भारतीय सेना को प्रतिवर्ष ₹250 करोड़ से अधिक के दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

## अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

- सरस स्वरोजगार योजना : इसके तहत 2,000 नए बूथ स्थापित किए गए हैं, जिनका विस्तार धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर किया जा रहा है। सरस को राष्ट्रीय ब्रांड बनाने के लिए दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी बूथ खोले जाने प्रस्तावित है।
- दूध में मिलावट की रोकथाम हेतु अभियान : 'सरस अमृतम अभियान' एवं 'दूध का दूध पानी का पानी अभियान'।
- मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना : इसके अंतर्गत दूध उत्पादकों को ₹5 प्रति लीटर की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- सरस सामूहिक बीमा योजना : दूध उत्पादकों को स्वास्थ्य सुरक्षा। इस योजना के तहत सामान्य बीमारी के लिए ₹1 लाख प्रति वर्ष तथा गंभीर बीमारी के लिए ₹2 लाख प्रति वर्ष का बीमा कवर दिया जाता है।
- राज सरस सुरक्षा कवच योजना : मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर ₹5 लाख तथा आंशिक विकलांगता पर ₹2.5 लाख रुपये दिए जाते हैं।

# Daily Current Affairs

Date : 30 April, 2026



- **सरस लाडो योजना** : योजना के अंतर्गत पंजीकृत दूध उत्पादकों की बेटियों की शादी के लिए ₹1 लाख का अनुदान।
- **सरस मायरा योजना** : डेयरी से जुड़े दुग्ध उत्पादकों की दो बेटियों की शादी के लिए मायरा के रूप में ₹21,000 की राशि प्रदान की जाती है।

## फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- पशुपालन और डेयरी विभाग की 'बेसिक एनीमल हस्बैंडरी स्टैटिस्टिक्स (BAHS) 2025' रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाद सम्पूर्ण देश में दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
- **शीर्ष - 5 दुग्ध उत्पादक राज्य** : उत्तर प्रदेश (15.66 प्रतिशत), राजस्थान (14.82 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (9.12 प्रतिशत), गुजरात (7.78 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (6.71 प्रतिशत)। ये सभी राज्य मिलकर देश के कुल दूध उत्पादन में 54.09 प्रतिशत का योगदान करते हैं।

--:6:--

## अंतरराष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव - 2026

### चर्चा में क्यों?

- 26 और 27 अप्रैल, 2026 को उदयपुर में 'अंतरराष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव' का आयोजन किया गया।



### मुख्य बिन्दु:

- आयोजक : कथक आश्रम उदयपुर द्वारा ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन (AIDA) के सहयोग से।
- महोत्सव के दौरान शास्त्रीय नृत्य की 7 विभूतियों को 'ताँबावती नगरी सम्मान' (उदयपुर का प्राचीन नाम) से सम्मानित किया गया।

--7--

# Daily Current Affairs

Date : 30 April, 2026



## सम्मानित विभूतियाँ :

नाम	शहर	नृत्य शैली
अमृत सिन्हा	लखनऊ	भरतनाट्यम
शरण्या बिष्ट	दिल्ली	कथक
राजश्री दास	बेंगलुरु	भरतनाट्यम
रिचा गुप्ता	दिल्ली	कथक
सृष्टि भसीन	जबलपुर	कथक
शिल्पा सिंह	जबलपुर	कथक
सुमि अजय	बिलासपुर	ओडिसी
विनय तिवारी	दिल्ली	भरतनाट्यम

--8--

## ✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p><b>जवाई लेपर्ड रिजर्व क्षेत्र में नए निर्माण पर रोक</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए पाली जिले के जवाई लेपर्ड रिजर्व क्षेत्र में सभी नए निर्माण कार्यों और खनन गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।</li><li>हाईकोर्ट ने तेंदुए के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के लिए 'यथास्थिति' (Status Quo) बनाए रखने का आदेश दिया है।</li></ul>
2.	<p><b>राजस्थान पुलिस का विशेष अभियान 'मिशन जागृति'</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>राजस्थान पुलिस का 'मिशन जागृति' मुख्य रूप से नशे के खिलाफ और अपराध नियंत्रण के लिए जयपुर में शुरू किया गया एक विशेष अभियान है।</li></ul>
3.	<p><b>16-कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परीक्षण</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेल कोच फैक्ट्री (RCF), कपूरथला द्वारा निर्मित पहली 16-कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का कोटा-नागदा-शामगढ़ रेलखंड पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया।</li><li>इस ट्रेन में फ्रांस की कंपनी अल्सटॉम की भारतीय इकाई द्वारा विकसित अत्याधुनिक प्रणोदन प्रणाली (Propulsion System) का उपयोग किया गया है।</li></ul>

4.	<p><b>यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>हाल ही में, राजस्थान में न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए 'यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम' की शुरुआत की गई।</li><li><b>उद्देश्य :</b> इस सिस्टम का उद्देश्य न्यायालयों में मामलों के पंजीकरण की प्रक्रिया को एक समान बनाना है, जिससे रिकॉर्ड प्रबंधन में आसानी हो।</li><li><b>शुभारंभ :</b> 25 अप्रैल, 2026 को जयपुर में आयोजित 'द बेंच बियॉड रिटायरमेंट' कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा।</li></ul>
5.	<p><b>'मन की बात' के 133वें संस्करण में 'गोडावण' का विशेष उल्लेख</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' के 133वें संस्करण (अप्रैल, 2026) में राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण (GIB) के संरक्षण प्रयासों की विशेष रूप से सराहना की।</li><li><b>गोडावण का वैज्ञानिक नाम :</b> अर्डोटिस निग्रिसेप्स (Ardeotis Nigriceps)</li><li><b>अन्य नाम :</b> सोन चिड़िया।</li><li><b>सर्वाधिक संख्या:</b> मरू राष्ट्रीय उद्यान (जैसलमेर), सांखलिया (अजमेर) तथा सोरसेन (बारां)</li><li><b>गोडावण प्रजनन केंद्र :</b> सुदासरी (जैसलमेर), सोरसेन (बारां) तथा जोधपुर।</li><li><b>गोडावण हैचिंग सेंटर (कृत्रिम प्रजनन केंद्र) :</b> रामदेवरा (जैसलमेर)</li></ul>
6.	<p><b>ऑपरेशन प्रवर्तन</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>जयपुर जिला प्रशासन और रसद विभाग द्वारा अवैध गैस रिफिलिंग, घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ 'ऑपरेशन प्रवर्तन' चलाया जा रहा है।</li></ul>

7.	<p><b>रीको द्वारा 12 नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान रीको द्वारा औद्योगिक इकाइयों को आगजनी जैसी आपदाओं से सुरक्षित रखने एवं बेहतर सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से 12 नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना तथा 37 अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।</li><li><b>प्रस्तावित अग्निशमन केंद्र :</b> चौपानकी, खुशखेड़ा (भिवाड़ी), करणी औद्योगिक क्षेत्र चरण प्रथम एवं द्वितीय (बीकानेर), बासनी, बोरानाडा (जोधपुर), चुरू, जैतपुरा (जयपुर), IID सेंटर एवं SGC परबतसर (नागौर), खेरदा (सवाई माधोपुर), टोंक, हिंडौन सिटी (करौली) तथा हनुमानगढ़ (चरण द्वितीय)।</li></ul>
8.	<p><b>डॉ. लोकेश सैनी : ए.बी. बेकर टीचर रिकग्निशन अवॉर्ड</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), जोधपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. लोकेश सैनी को अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी (AAN) द्वारा 'ए.बी. बेकर टीचर रिकग्निशन अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया।</li><li>यह सम्मान उन्हें न्यूरोलॉजी शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। डॉ. सैनी वर्ष 2026 के पुरस्कार हेतु चयनित होने वाले एकमात्र भारतीय हैं।</li></ul>
9.	<p><b>अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय हैंडबॉल (पुरुष) चैंपियनशिप 2025-26</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>आयोजन :</b> राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में 21 से 25 अप्रैल, 2026 तक।</li><li><b>विजेता :</b> राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने 14 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता।</li></ul>



## राष्ट्रीय परिदृश्य



### शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम



#### चर्चा में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत छात्रों के अनिवार्य प्रवेश संबंधी प्रावधान को उचित ठहराया।



#### मुख्य बिन्दु:

- उच्चतम न्यायालय ने लखनऊ पब्लिक स्कूल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले में यह निर्णय दिया कि नेबरहुड स्कूल RTE अधिनियम, 2009 के तहत पात्र छात्रों को तत्काल प्रवेश देने के लिए बाध्य हैं।

## निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009

- **संवैधानिक आधार:** इसे संविधान के अनुच्छेद 21A को प्रभावी बनाने के लिए लागू किया गया।
- **अनुच्छेद 21A:** इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। यह अनुच्छेद सभी बालकों (6-14 वर्ष) को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
- **प्रमुख प्रावधान:** RTE अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक नेबरहुड स्कूल में प्रत्येक बच्चे (6-14 वर्ष) को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है।
- **25% आरक्षण का प्रावधान:** समावेशी और समतापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% आरक्षण अनिवार्य है।
- इसके बदले स्कूलों को प्रति छात्र व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य द्वारा की जाती है।

## INS कल्पेनी

### चर्चा में क्यों?

- भारतीय नौसेना का एक फास्ट अटैक क्राफ्ट, INS कल्पेनी, अड्डू एटोल पहुंच गया है। यह भारत और मालदीव के बीच जारी सामुद्रिक सहयोग की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।



### मुख्य बिन्दु:

- INS कल्पेनी कार-निकोबार श्रेणी का वाटरजेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है। इसे 2010 में कमीशन किया गया था।
- इसका नाम लक्षद्वीप समूह के कल्पेनी द्वीप के नाम पर रखा गया है।

### अड्डू एटोल

- यह मालदीव का सबसे दक्षिणी एटोल है। यह मध्य हिंद महासागर में चागोस द्वीपसमूह के उत्तर में स्थित है।

## आर्थिक घटनाक्रम

### जैविक खेती

#### चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री ने कहा कि सिक्किम की जैविक खेती देश के लिए एक मॉडल है। सिक्किम राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सिक्किम भारत के जैविक खाद्य मिशन का नेतृत्व कर रहा है।

#### मुख्य बिन्दु:

#### जैविक खेती (Organic Farming)

- यह एक संधारणीय कृषि प्रणाली है। इसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और अनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों का उपयोग करने से बचा जाता है।
- इसमें फसल चक्र, फसल अवशेष, पशुजन्य खाद और अन्य जैविक संसाधनों का उपयोग किया जाता है।

#### लाभ:

- किसानों की कृषि लागत कम होती है।
- मृदा की गुणवत्ता और जैव विविधता में सुधार होता है।
- स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और रसायन-मुक्त खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं।
- जल प्रदूषण कम होता है।



## जैविक खेती का सिक्किम मॉडल

- इस राज्य ने 2010 में सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन शुरू किया और 2016 तक विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया।
- सिक्किम को जैविक कृषि में उसके नेतृत्व के लिए 2018 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा 'फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड' से भी सम्मानित किया गया।

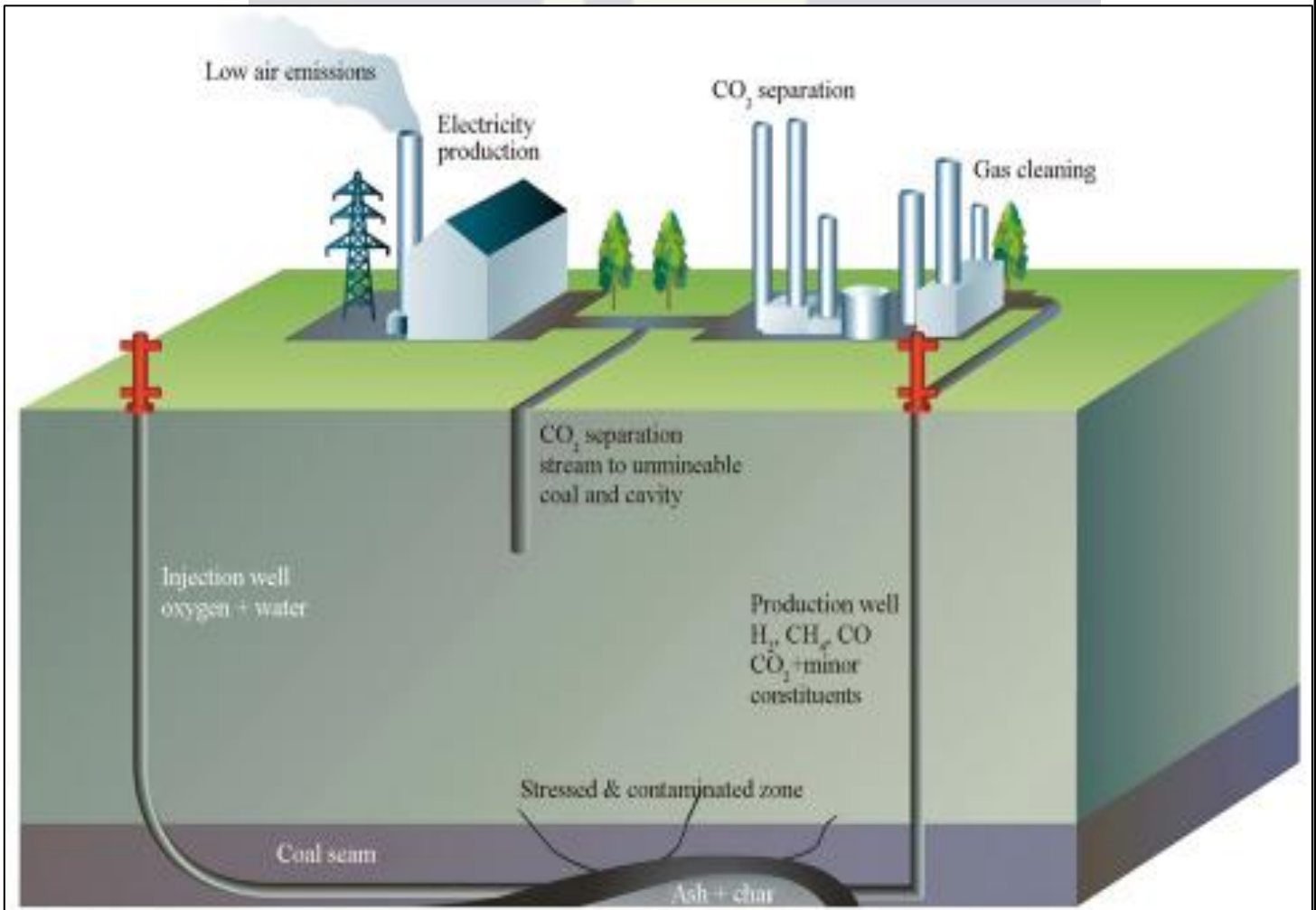
## जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख पहलें:

- **सिक्किम राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी:** यह जैविक कृषि की निगरानी और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।
- **कृषि नीतियाँ:** जैविक बीज, वित्तपोषण (अनुदान, सब्सिडी), इनपुट और स्थानीय उत्पादन प्रणालियों को बढ़ावा देने के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।
- **बाजार पहुँच:** किसानों को घरेलू और वैश्विक बाजारों में जैविक उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास किया गया है।

## भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG)

### चर्चा में क्यों?

- भारत ने पहली बार भूमिगत कोयला गैसीकरण तकनीक से जुड़े कोयला खनन की शुरुआत की है, जिसके तहत चार वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों के लिए समझौते किए गए हैं।



### मुख्य बिन्दु:

- भूमिगत कोयला गैसीकरण वास्तव में एक स्व-स्थाने प्रक्रिया है, जिसमें कोयले को जमीन के अंदर ही गैस में बदल दिया जाता है। इससे पारंपरिक खनन (खोदकर निकालने) की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे लागत और पर्यावरणीय नुकसान, दोनों कम हो सकते हैं।

## कोयला गैसीकरण

- यह एक ऊष्मा-रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोयले को गैस के मिश्रण में बदला जाता है, जिसे सिंथेसिस गैस कहा जाता है।
- यह मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से बनी होती है।
- इस सिनगैस का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है, या फिर इससे सिंथेटिक ईंधन और उर्वरक बनाए जा सकते हैं।
- कोल गैसीकरण से कोयले का अपेक्षाकृत स्वच्छ उपयोग संभव होता है। इससे बनने वाली सिनगैस का उपयोग बिजली उत्पादन, मेथनॉल, अमोनिया, यूरिया और तरल ईंधन बनाने में किया जा सकता है।
- भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन' शुरू किया है। इसका लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना है।



## अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य



### एशिया-प्रशांत फोरम



#### चर्चा में क्यों?

- भारत ने 'सतत विकास के लिए भू-स्थानिक आधारों को आगे बढ़ाने पर एशिया-प्रशांत फोरम' की मेजबानी की।



**ASIA PACIFIC FORUM**  
ADVANCING HUMAN RIGHTS IN OUR REGION



#### मुख्य बिन्दु:

- इस फोरम में रेखांकित किया गया कि कैसे भू-स्थानिक प्रणालियाँ (Geospatial Systems) 'फ्यूचर रेडी गवर्नेंस' की कुंजी बन गई हैं।
- इसमें UN-GGIM (वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन पर विशेषज्ञों की संयुक्त राष्ट्र समिति) के तहत वैश्विक ढाँचे के महत्त्व पर भी जोर दिया गया।
- UN-GGIM संस्था भू-स्थानिक नीति निर्धारण के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करती है। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के तहत विशेषज्ञों की एक समिति के रूप में संचालित होती है।

#### भू-स्थानिक प्रणाली

- ये ऐसे उपकरण हैं जो स्थान/अवस्थिति से जुड़े आंकड़ों को एकत्र करने, विश्लेषण करने और प्रदर्शित करने के लिए बनाए गए हैं।
- इनमें सैटेलाइट इमेजरी और रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS), ड्रोन और LiDAR जैसी विभिन्न भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का समावेश होता है।

## चांगी नौसैनिक अड्डा



### चर्चा में क्यों?

- इंडियन ओशन शिप (IOS) सागर, INS सुनयना, सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे पर पहुँचे।



### मुख्य बिन्दु:

#### चांगी नौसैनिक अड्डा

- **रणनीतिक अवस्थिति:** यह मलक्का जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर तक सीधी पहुँच प्रदान करता है।
- भारत और सिंगापुर के बीच 2017 के लॉजिस्टिक्स समझौते के तहत भारतीय नौसेना को लॉजिस्टिक सहायता के लिए इस अड्डे तक पहुँच प्रदान की गई है।

#### भारत की रणनीतिक उपस्थिति वाले अन्य विदेशी बंदरगाह

- **डुकम बंदरगाह:** दक्षिण-पूर्व ओमान में, अरब सागर के पश्चिमी तट पर अवस्थित है।
- **सबांग बंदरगाह:** इंडोनेशिया में सुमात्रा के उत्तरी छोर पर, मलक्का जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार पर।
- **अन्य बंदरगाह:** चाबहार बंदरगाह (ईरान); हाइफ्रा बंदरगाह (इजराइल); सित्वे बंदरगाह (म्यांमार); चटगांव और मोंगला बंदरगाह (बांग्लादेश)।

--:20:--

## सिंधु जल संधि

### चर्चा में क्यों?

- पाकिस्तान ने भारत की जल विद्युत परियोजनाओं पर अपनी आपत्तियों का दायरा बढ़ाते हुए चिनाब नदी पर कीरू और कावर जल विद्युत परियोजनाओं को भी शामिल कर लिया है। हालांकि, ये परियोजनाएँ औपचारिक रूप से सिंधु जल संधि के तहत मध्यस्थता के दायरे में नहीं आती हैं।



### मुख्य बिन्दु:

#### सिंधु जल संधि (IWT)

- इस संधि पर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षर किए गए थे।
- पूर्वी नदियाँ (रावी, व्यास, सतलुज): अबाध उपयोग के लिए भारत को पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया।

# Daily Current Affairs

Date : 30 April, 2026



- **पश्चिमी नदियां (सिंधु, झेलम, चिनाब):** इन नदियों का जल मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित किया गया है, जिन पर भारत को भी सीमित अधिकार दिए गए हैं।

**IWT के तहत विवाद समाधान-तंत्र (त्रिस्तरीय श्रेणीबद्ध तंत्र)**

- **स्थायी सिंधु आयोग (PIC):** यह प्रथम स्तर का निकाय है। इसमें भारत और पाकिस्तान जल से जुड़े आंकड़ों का आदान-प्रदान करते हैं और संधि की व्याख्या या संभावित उल्लंघनों से जुड़े सवालों का समाधान करते हैं।
- **तटस्थ विशेषज्ञ:** किसी मुद्दे को जब स्थायी सिंधु आयोग (PIC) समाधान करने में विफल रहता है, तो तकनीकी विवादों को हल करने के लिए (विश्व बैंक या भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से) तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाती है।
- **माध्यस्थम अधिकरण:** यह स्थायी सिंधु आयोग या तटस्थ विशेषज्ञ स्तरों पर अनसुलझे विवादों को कानूनी रूप से हल करने के लिए 7-सदस्यीय अधिकरण है।

-:22:-

## OPEC एवं OPEC+

### चर्चा में क्यों?

- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) और OPEC+ से बाहर निकलने की घोषणा की।

### मुख्य बिन्दु:

#### OPEC

- यह तेल निर्यातक देशों का एक स्थायी अंतर-सरकारी संगठन है।
- **स्थापना:** इसकी स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने की थी।
- अन्य सदस्यों में अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, लीबिया और नाइजीरिया शामिल हैं।
- **मुख्यालय:** वियना (ऑस्ट्रिया)
- **उद्देश्य:** सदस्य देशों में पेट्रोलियम से जुड़ी नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना, और पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित व स्थिर मूल्य सुनिश्चित करना।
- **OPEC+:** अमेरिकी शेल तेल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण तेल की गिरती कीमतों से निपटने के लिए, ओपेक के सदस्य देशों ने 2016 में ओपेक+ के गठन के लिए 10 अन्य तेल उत्पादक देशों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
- ओपेक के सदस्य देशों के अलावा इसमें रूस, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मैक्सिको, मलेशिया, ओमान, दक्षिण सूडान और सूडान शामिल हैं।

## 2026 शंघाई सहयोग संगठन (SCO) रक्षा मंत्रियों की बैठक

### चर्चा में क्यों?

- किर्गिस्तान में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में बोलते हुए, रक्षा मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ SCO की एकीकृत कार्रवाई का आह्वान किया और दोहरे मापदंडों के खिलाफ चेतावनी दी।

### मुख्य बिन्दु:

#### शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

- शंघाई फाइव का उदय 1996 में पूर्व सोवियत संघ के 4 गणराज्यों और चीन के बीच सीमांकन और विसैन्यीकरण वार्ता की एक श्रृंखला के परिणामस्वरूप हुआ था।
- कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई फाइव के सदस्य थे।
- 2001 में उज्बेकिस्तान के समूह में शामिल होने के साथ ही, शंघाई फाइव का नाम बदलकर SCO कर दिया गया।
- उद्देश्य:** मध्य एशियाई क्षेत्र में आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ पर अंकुश लगाने के प्रयासों के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना।
- सदस्य (10):** चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस और मध्य एशिया के चार देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान।
- भारत 2017 में पूर्ण सदस्य बना।
- सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% और विश्व की लगभग 40% जनसंख्या का योगदान करते हैं।
- पर्यवेक्षक का दर्जा:** अफगानिस्तान और मंगोलिया।

## पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

### झील: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट

#### चर्चा में क्यों?

- कैग की एक रिपोर्ट के अनुसार जम्मू और कश्मीर में झीलें तेजी से विलुप्त हो रही हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 1967 के बाद से 518 झीलें या तो पूरी तरह से विलुप्त हो गई हैं या काफी छोटी हो गई हैं।

#### मुख्य बिन्दु:

- जम्मू-कश्मीर की निम्नलिखित प्रमुख झीलें खतरे का सामना कर रही हैं:
  - वुलर झील: भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील।
  - डल झील: श्रीनगर की प्रसिद्ध झील, जो पर्यटन का केंद्र है।
  - मानसबल झील: कश्मीर की सबसे गहरी झील।
  - होकरसर झील, सुरिनसर झील और मानसर झील।

#### झीलों के समक्ष संकट के कारण:

- प्रदूषण और सुपोषण
- अतिक्रमण और भूमि उपयोग में परिवर्तन
- जलग्रहण क्षेत्र का क्षरण और तलछट जमना
- संस्थाओं और प्रशासन की उदासीनता
- इंसानी गतिविधियों का दबाव

#### भारत में झीलों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

- राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम: वर्ष 1985-86 में प्रारंभ इस कार्यक्रम के तहत राज्यों को आर्द्रभूमियों (झीलों सहित) के निम्नीकृत होने से बचाने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।
- राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम: वर्ष 2001 में प्रारंभ इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी और अर्ध-शहरी झीलों की पारिस्थितिकी और जल गुणवत्ता में सुधार करना है।
- राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण कार्यक्रम: वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया।

## आर्द्रभूमि नियमावली, 2017:

- इसके नियम “विवेकपूर्ण उपयोग” के सिद्धांत पर आधारित हैं।
- ये नियम आर्द्रभूमियों के संरक्षण और संधारणीय उपयोग के लिए विनियामक ढांचा प्रदान करते हैं।
- ये नियम आर्द्रभूमियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए राज्य स्तर पर प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करते हैं।

## अन्य कानून:

- **जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974:** यह जल निकायों में सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट के प्रवाह को नियंत्रित करता है।
- **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986:** यह मुख्य कानून है, जिसके आधार पर आर्द्रभूमि नियमावली और पर्यावरण संरक्षण मानक बनाए गए हैं।
- **रामसर कन्वेंशन, 1971:** इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों का संरक्षण है।